दैनिक जागरण
अपनी प्रसन्नता के निर्धारक आप स्वयं होते हैं

आयुष्मान की चुनौतियां

इस पर आश्चर्य नहीं कि एक अमेरिकी थिंक टैंक ने भी मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को तारीफ के काबिल पाया। इसके पहले अन्य देशी-विदेशी संस्थाएं भी इस योजना को बेहतर बता चुकी हैं। चूंकि निर्धन वर्ग के परिवारों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली यह योजना गरीबों के लिए राहतकारी साबित हो रही है इसलिए उसका बखान कर चुनावी लाभ लेने की भी कोशिश हो रही है। इसमें हर्ज नहीं। सरकारों का यह अधिकार है कि वे अपनी सफल योजनाओं का गुणगान करते हुए राजनीतिक लाभ अर्जित करने की कोशिश करें। इस योजना की लोकप्रियता इससे साबित होती है कि बहुत कम समय में लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के सकारात्मक असर से इन्कार नहीं, लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या फिलहाल कारगर साबित होती दिख रही यह योजना देश में आवश्यक स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण करने में सफल हो रही है? निःसंदेह यह इस योजना का मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है, लेकिन केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है। किसी को यह देखना चाहिए कि जरूरी स्वास्थ्य ढांचे का भी निर्माण हो। यह सुनिश्चित करते समय इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के साथ सरकारी स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण और विस्तार होना बहुत आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इतने बड़े देश में सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाए बिना अभीष्ट की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

यह सही है कि फिलहाल गरीबों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है, लेकिन अगर स्वास्थ्य ढांचे को विस्तार नहीं दिया जा सका तो गरीबी रेखा से इतर लोगों के लिए उपचार महंगा हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने वाले धन का अधिकांश हिस्सा इस योजना में ही खप जाने का भी अंदेशा है। यह अंदेशा इसलिए और है, क्योंकि अभी कुल जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होता है। इस खर्च को बढ़ाए जाने और उसका एक हिस्सा सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को विकसित करने में किया जाना चाहिए। यह काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो तमाम रोगों का घर बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक ओर जहां गरीब तबका कुपोषण से ग्रस्त है वहीं मध्य और धनी वर्ग रहन-सहन की उन आदतों से ग्रस्त है जो बीमारियों का कारण बनती हैं। स्पष्ट है कि किसी को इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि औसत भारतीय अपने खान-पान, रहन-सहन को लेकर सतर्क रहें। मोदी सरकार को केवल इससे खुश नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी थिंक टैंक ने आयुष्मान योजना की तारीफ कर दी, क्योंकि उसने इस योजना की कुछ चुनौतियां भी रेखांकित की हैं। यह सही है कि हर नई योजना में प्रारंभ में कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन जब यह कहा जा रहा है कि लागत को कम करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है तो फिर उस पर ध्यान देना वक्त की मांग है।

प्रतिनियुक्ति का खेल

झारखंड में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दूसरे स्कूलों या अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्त सभी प्राथमिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद करने का आदेश दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे लेकर न केवल निर्देश दिया है, बल्कि प्रतिनियुक्ति रद करने की रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें उन्हें लिखना होगा कि उनके जिले में कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नही है। यह कार्रवाई तब हुई जब विधानसभा के लंबित आश्वासनों की समीक्षा में यह बात सामने आई कि विभिन्न जिलों में कई शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिले के अन्य स्कूलों या अन्य जिलों में की गई है। इसके बाद विभाग के प्रधान सचिव ने निदेशक को तत्काल सभी प्रतिनियुक्ति रद करने का आदेश दिया। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद करने का आदेश एक सराहनीय पहल है, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि प्रतिनियुक्ति का यह खेल भविष्य में फिर से शुरू न हो। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद करने के आदेश पहले भी अधिकारियों द्वारा दिए जाते रहे हैं। शुरू में इसका आंशिक अनुपालन होता है बाद में फिर से यह खेल शुरू हो जाता है। शिक्षकों के मूल स्कूल से किसी अन्य स्कूल में प्रतिनियुक्ति से मूल स्कूल में बच्चों का पठन-पाठन बाधित होता है। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक मनचाहे स्कूल में स्थानांतरण नहीं होने पर अपनी पैरवी-पहुंच से शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति करा लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में आवश्यक शिक्षक नहीं मिल पाते। दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम रहती है, जबकि शिक्षक अधिक हो जाते हैं। कई शिक्षक अपनी प्रतिनियुक्ति करा लेते हैं, जिससे वे अपना मूल काम छोड़कर लिपिकीय कार्य में लग जाते हैं। प्रतिनियुक्ति का खेल माध्यमिक व प्लस टू स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर होता है। इन शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति रद हो तो यह भी सुनिश्चित हो कि वहां आवश्यक शिक्षक उपलब्ध हों। ऐसा न हो कि प्रतिनियुक्ति रद करने के बाद शिक्षकों की कमी हो जाए। यदि ऐसा होता है तो वहां किसी दूसरे शिक्षक की नियुक्ति भी हो। अन्यथा प्रतिनियुक्ति रद करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

सार्थक संवाद के बजाय वाद-विवाद

संजय गुप्त

पता नहीं पीएम को चोर बताने और उसके जवाब में राजीव गांधी पर निशाना साधने से कांग्रेस और भाजपा को क्या हासिल होगा, लेकिन बेहतर यह होता कि इस सबसे दूर रहते हुए भ्रष्टाचार पर कोई सार्थक बहस की जाती

चुनावी लड़ाई तेज होते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का अपना जो नारा उछालना शुरू किया था उसे वह किस हद तक ले गए, इसका एक प्रमाण गुरुग्राम की एक रैली में मिला। इस रैली में उन्होंने कहा कि सेना में काम करने वाले हरियाणा के जवानों के पैसे चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अनिल अंबानी के खाते में तीस हजार करोड़ रुपये डाले। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने नीरव मोदी के खाते में 45 हजार करोड़ रुपये और विजय माल्या के खाते में 10 हजार करोड़ रुपये डाले। राहुल गांधी की मानें तो मोदी ने अपने मित्र उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्जे भी माफ कर दिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को भ्रष्ट बताने के लिए इसी तरह के भाषण एक अर्से से दे रहे हैं, लेकिन इसके सुबूत देने की जरूरत नहीं समझ रहे कि आखिर कब और किस खाते से प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी या फिर नीरव अथवा विजय माल्या के खाते में पैसे डाले? अगर ऐसा हुआ जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसके कोई सुबूत भी तो होंगे। ऐसे कोई सुबूत देने के बजाय राहुल गांधी प्रधानमंत्री को भ्रष्ट साबित करने के अपने अभियान में इसके बावजूद जुटे हैं कि न तो सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में गड़बड़ी की बात मानी और न ही कैग ने।

राहुल गांधी केवल प्रधानमंत्री को चोर ही नहीं बता रहे, बल्कि उनके खिलाफ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि इसने चोरी की है... यह पकड़ा जाएगा...भाग जाएगा। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी तब परेशान हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मिस्टर क्लीन की छवि के साथ आए थे, लेकिन उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर वन की तरह हुआ। प्रधानमंत्री के इस बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह कहा कि मोदीजी, लड़ाई खत्म हो चुकी है, आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा, लेकिन उन्होंने चौकीदार चोर है कहना नहीं छोड़ा। इसके बावजूद नहीं छोड़ा कि उन्हें इस गलतबयानी के लिए लिखित माफी मांगनी पड़ी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगने के बाद भी राहुल चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से राजीव गांधी को निशाने पर लिया और उनकी ओर से आइएनएस विराट के जरिये छुट्टियां मनाने के विषय को उठा दिया। हालांकि नौसेना के कुछ पूर्व अधिकारियों ने कहा कि राजीव गांधी ने छुट्टियां मनाने के लिए नौसेना के युद्धपोत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ ने माना कि इस्तेमाल किया था। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच उस दौर की खबरें यही संकेत करती हैं कि राजीव गांधी जब समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने गए थे तो आइएनएस विराट की सेवाएं ली गई थीं। यह भ्रष्टाचार का प्रसंग तो नहीं, लेकिन नौसेना के अनावश्यक इस्तेमाल का मामला बनता है।

हालांकि लगता यही है कि अपने प्रति राहुल गांधी की अपमानजनक शब्दावली से आजिज आकर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को निशाने पर लिया, लेकिन यह बहस का विषय तो है ही कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? प्रधानमंत्री होने के नाते तो उन्हें कोई नई नजीर पेश करनी चाहिए थी। राजीव गांधी पर मोदी की टिप्पणी के बाद ऐसे तर्क दिए गए कि दिवंगत व्यक्तियों के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। इस तर्क को निराधार नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह किसी एक पक्ष पर लागू नहीं हो सकता। आखिर यह राहुल ही थे जो कुछ समय पहले स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को कायर और अंग्रेजों के पैर छूने वाला बता रहे थे। यह भी एक तथ्य है कि मनोहर पर्रीकर के निधन पर ऐसे बयान सामने आए कि वह राफेल सौदे का पहला शिकार बने। यदि राहुल अपने और अपनों के लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं तो उन्हें दूसरों के लिए भी ऐसे ही अधिकार की वकालत करनी होगी। अगर राहुल और उनके सहयोगी यह मानते हैं कि बोफोर्स सौदे में कुछ गलत नहीं हुआ तो इससे यह हकीकत छिपने वाली नहीं कि इस सौदे में दलाली की रकम के इधर-उधर होने के सुबूत सामने आ गए थे। ऐसे सुबूतों के कारण ही 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था।

अवधेश राजपूत

बोफोर्स मामले में यह भी जगजाहिर है कि इटैलियन कारोबारी क्वात्रोची को देश से रातों-रात भगाया गया और फिर स्वीडन सरकार से गुपचुप रूप से यह अनुरोध किया गया कि भारत सरकार इस मामले में जांच नहीं चाहती। यह अनुरोध करने वाले तबके विदेश मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कांग्रेस चाहे जो दावा करे, सच यही है कि बोफोर्स सौदे की जांच ढंग से नहीं होने दी गई। इसी कारण सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचा जा सका। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि बोफोर्स के अलावा उसके शासनकाल में हुए अन्य रक्षा सौदे भी संदेह के घेरे में आए। वीवीआइपी हेलीकाप्टर सौदे का मामला तो अदालत में ही है।

यह समझ आता है कि कांग्रेस राफेल सौदे को बोफोर्स सरीखा बनाना चाहती है, लेकिन उसकी मुश्किल यह है कि उसके पास इस सौदे में गड़बड़ी के कहीं कोई सुबूत नहीं। यह सही है कि चुनाव के दौरान आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं और कई बार भाषा की मर्यादा भी टूटती है, लेकिन यह साफ है कि इस बार भाषा की मर्यादा का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन हो रहा है। इसके दुष्परिणाम सामने आने ही थे और वे राजनीतिक कटुता के रूप में दिख रहे हैं। लोकतंत्र की अपनी एक भाषा होती है। अगर उसके स्तर को लेकर सतर्क नहीं रहा जाएगा तो फिर तू तू-मैं मैं ही देखने को मिलेगा। पता नहीं प्रधानमंत्री को चोर बताने और उसके जवाब में राजीव गांधी पर निशाना साधने से कांग्रेस और भाजपा को क्या हासिल होगा, लेकिन बेहतर यही होता कि इस सबसे बचा जाता और भ्रष्टाचार पर कोई सार्थक बहस होती। यह बहस इसलिए होनी चाहिए थी, क्योंकि भ्रष्टाचार देश की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। मोदी सरकार में भले ही उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रित दिखा हो, लेकिन निचले स्तर का भ्रष्टाचार तो जस का तस है। ध्यान रहे कि इसी भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त है।

इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी को यह बात चुभी होगी कि उनके दिवंगत पिता पर निशाना साधा गया, लेकिन क्या उन्होंने यह सोचा कि उनके अनर्गल आरोपों से प्रधानमंत्री को कैसा लगता होगा? यह संभव नहीं कि राहुल अपने विरोधियों के खिलाफ तो कुछ भी कहने का अधिकार रखना चाहें, लेकिन इसी के साथ यह भी चाहें कि उन्हें या उनके करीबियों के खिलाफ कुछ न कहा जाए। आज के दौर में लोकतंत्र में यह संभव नहीं।

response@jagran.com

देश बदलने के लिए दलबदल

हास्य-व्यंग्य

अनुज त्यागी

जो दल नहीं बदल सकता वह देश क्या खाक बदलेगा? दल बदलना तो कई समस्याओं का समाधान है

स्वागत है। आज डिबेट में हमारे साथ हैं चरणदास जी, जो आलतू-फालतू दल के उम्मीदवार हैं और नैनसुख जी जो चलता-फिरता दल के सचिव हैं। फन्नी चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मंच के प्रपंच' में आप दोनों का स्वागत है। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चरणदास जी आपसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आप के चरण किसी एक जगह नहीं टिकते, मतलब आप दल बदलते रहते हैं। क्या कहना है आपको?

अपना एक चरण दूसरे चरण पर टिकाते हुए चरणदास बोले, आप भ्रम के शिकार हो गए। हम किसी नए दल में नहीं जाते। दल हमारे पास आते हैं और फिर, रूप अलग-अलग होते हुए भी सबका स्वरूप एक ही है। सरल भाषा में ऐसे समझिए अलग-अलग होते हुए भी हम एक हैं और एक होते हुए भी अलग-अलग हैं। देख लेना, हमारा आलतू-फालतू दल ही सरकार बनाएगा, कई वे दल हमें अभी से सरकार बनाने का ऑफर दे रहे हैं जिनमें मैं पहले रह चुका हूं।

नैनसुख जी आपको क्या लगता है, जनता को आपको क्यों चुनना चाहिए?

देखिए, विरोधी दल झूठा है। इन्होंने जनता के दर्द को कभी अपना दर्द नहीं समझा। इन्होंने 5000 बार झूठ बोला है।

माफ कीजिएगा नैनसुख जी, यह तो इनकी बात हो गई, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, जनता जानना चाहती है, वह आपको क्यों चुने?

देखिए, कम से कम आप तो समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इन्होंने 5001 बार झूठ बोला है, ये जनता का दर्द नहीं समझते।

नैनसुख जी विपक्षी आप पर भी दलबदलू प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं।

देखिए लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो ऐसा कह रहें हैं वे कुएं के मेंढक हैं। जनता जानती है कि जो दल नहीं बदल सकता, वह देश क्या खाक बदलेगा। मैं आपको समझाता हूं, दल बदलना कई समस्याओं का हल है। यह फार्मूला दिल्ली वाले भी अपना सकते हैं जी। मैंने अखबार में पढ़ा है, प्रदूषण से दिल्लीवासियों का दम घुट रहा है, उन्हें शहर बदल देना चाहिए। नेताओं का जब एक दल में दम घुटने लगता है तो वे भी यही करते हैं।

चरणदास जी, बेरोजगारी से निपटने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?

आपने बिल्कुल मेरे मन का सवाल पूछ लिया, यही है असली मुद्दा। जब हमारी सरकार थी तो हमने बेरोजगारों के लिए अलग से अखबार बेरोजगार टाइम्स शुरू किया जो दिखाता है कि हम बेरोजगारी के लिए कितने सजग रहे। अबकी बार हमारी सरकार आई तो हम प्राइम डिबेट कराएंगे, बेरोजगारी विशेषांक पत्रिका छपवाएंगे और जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को यूएन में भी लेकर जाएंगे।

चरणदास जी, आरोप है कि आप कुछ ज्यादा ही लंबी फेंकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?

इसका जवाब जनता को समझना पड़ेगा। यह दूरी पर निर्भर करता है। जैसे क्रिकेट में सर्कल के अंदर खड़े फील्डर को कम दूर तक बॉल फेंकनी होती है, लेकिन बाउंड्री पर तैनात फील्डर को लंबी फेंकनी पड़ती है। इसी तरह भाषण में ध्यान रखना पड़ता है कि बात अंतिम आदमी तक पहुंचे। आप जानते हैं मेरी रैली में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए मुझे अंतिम आदमी तक बात पहुंचाने के लिए लंबी फेंकनी पड़ती है।

चरणदास जी, शिक्षा व्यवस्था समाज के लिए अहम होती है, लेकिन आपने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया?

देखिए, ऐसा है कि हमने शिक्षा के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए और उनसे काफी सुधार भी हुआ। आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आज शिक्षा में सुधार से ज्यादा उधार की जरूरत है।

नैनसुख जी भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था के लिए नासूर बन चुका है। सड़क निर्माण का पेमेंट होता नहीं, उससे पहले सड़कें टूट जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?

ऐसा नहीं है, आपको हर चीज नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आदत पड़ गई है। सड़कें एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। आप देखते नहीं जैसे ही बरसात होती है तो उसका असर सब पर पड़ता है। कोई भी अछूता नहीं रहता- न पक्षी, न पहाड़ और न पेड़। आखिर कुछ तो असर सड़क पर भी पड़ेगा। आप क्या यह चाहते हैं कि बारिश हो, लेकिन उसका असर धरती पर न पड़े?

response@jagran.com

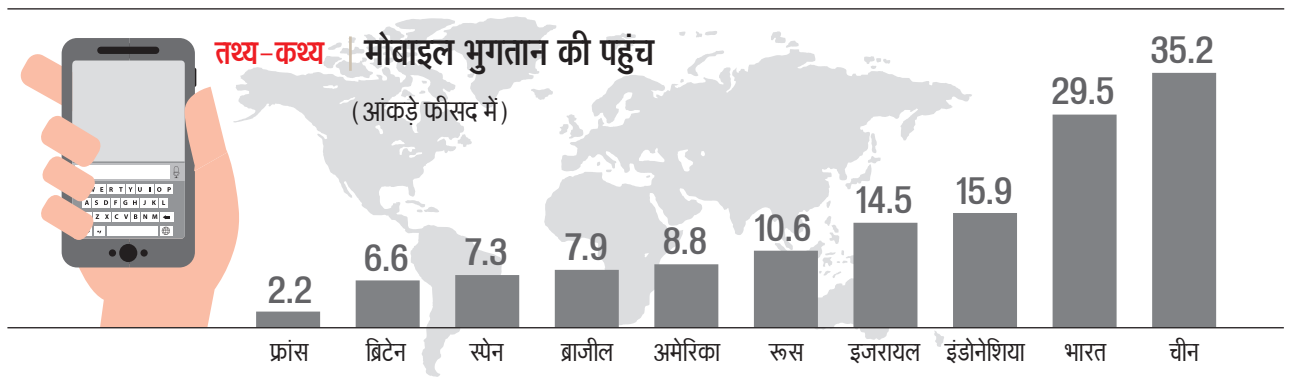

ऊर्जा

संघर्ष की सार्थकता

मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपनी स्थितियों, परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। वह अपनी असफलता और हार का कारण अक्सर इन्हीं कारकों को ठहराता है। वहीं जो लोग इनके बजाय स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं, वे प्रोएक्टिव या सकारात्मक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। ये सामान्य लोगों से अलग दिखते हैं और अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए पहल करने की शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों के समक्ष समर्पण नहीं करते। विपरीत परिस्थितियां वास्तव में हमारे लिए अवसरों की खान बनकर आती है। सिर्फ उनका आवरण कुछ कठोर होता है। ऐसे में हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करके हम मुश्किलों का रुख मोड़ देते हैं।

परिस्थितियों के आगे हार मान लेना आसान होता है। इससे व्यक्ति दूसरों की दृष्टि में खुद को दया का पात्र बना लेता है। परिस्थितियों से लड़कर खुद को मजबूत बनाना इतना कठिन भी नहीं है। बस इसके लिए व्यक्ति के भीतर प्रोएक्टिव का गुण होना बहुत जरूरी है। अधिकतर व्यक्ति रिएक्टिव प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए वे परिस्थितियों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति हर तरह की स्थिति में भरपूर संघर्ष करते हैं। जीवन की एक सच्चाई यह है कि व्यक्ति अगर चाहे तो कोई भी उसे दुखी या परेशान नहीं कर सकता। प्रोएक्टिव लोग धैर्य और बुद्धिमता से हर परिस्थिति को सुलझाना और उसे अपने पक्ष में करना जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रोएक्टिव बन सकता है। केवल 30 दिनों तक प्रोएक्टिविटी के सिद्धांत को आजमाकर जीवन में बड़े-बड़े गुणकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके लिए बस आप छोटे-छोटे वादे करें और उन्हें निभाएं। अपने पथप्रदर्शक बनें, मूल्यांकनकर्ता न बनें। आदर्श बनें, आलोचक न बनें। समाधान का हिस्सा बनें, समस्याएं उत्पन्न न करें और जिम्मेदारी से परिस्थितियों का सामना करें। केवल तीस दिन ऐसा करने से आप अपने व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन पाएंगे। यह परिवर्तन आपकी एक अलग पहचान बनाएगा। जीवन में हर परिस्थिति का सकारात्मक मुकाबला करके ही जिंदगी का वास्तविक आनंद लिया जा सकता है। यही संघर्ष जीवन को सार्थकता प्रदान करता है।

रेनू सैनी

सागर में मंडराता विकिरण का खतरा

मुकुल व्यास

परमाणु परीक्षणों से निकले रेडियोएक्टिव कण गहरे समुद्र तक पहुंच रहे हैं। खाद्य शृंखला भी इसकी चपेट में आ रही है

परमाणु बम परीक्षणों के बाद वायुमंडल में छूटने वाला रेडियोएक्टिव कार्बन समुद्र के सबसे गहरे स्थानों पर पहुंच गया है। एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं ने परमाणु बम परीक्षणों के उपरांत निकलने वाले रेडियोएक्टिव कार्बन के क्रस्टेशियन जीवों के मसल टिशू में पहुंचने का पहला प्रमाण जुटाया है। ये जीव समुद्री खाइयों में रहते हैं। इन खाइयों में मेरियाना ट्रेंच भी शामिल है जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। ध्यान रहे कि झींगा मछली और केकड़े जैसे जीव क्रस्टेशियन समूह से संबद्ध हैं। पता लगा है कि समुद्री सतह पर रहने वाले जीवों ने 1950 के दशक में ही परमाणु बम के कार्बन को अपने शरीर के मॉलिक्यूल्स में शामिल कर लिया था।

एक नए अध्ययन के अनुसार गहरे समुद्र की खाइयों में रहने वाले क्रस्टेशियन जीव समुद्री सतह पर गिरने वाले जीवों के कार्बनिक पदार्थ की खुराक ग्रहण कर रहे हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि मानव प्रदूषण बहुत शीघ्र खाद्य चक्र में प्रविष्ट होकर गहरे समुद्र तक पहुंच सकता है। चीनी विज्ञान अकादमी के भू-रसायनशास्त्री डॉ. निंग वांग का कहना है कि समुद्री प्रवाह को बम कार्बन युक्त जल को सबसे गहरी समुद्री खाई तक पहुंचाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन खाद्य शृंखला यह काम बहुत तेजी से करती है। जैविक प्रणालियों के संदर्भ में सतह और तल के बीच गहरी अंतरक्रिया होती है। मनुष्य की गतिविधियां 11,000 मीटर नीचे तक जैविक प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं।

अतः हमें अपने आचरण के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस शोध टीम का कहना है कि इन नतीजों से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि गहरे समुद्र में पोषक तत्वों के अभाव में जीव किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शोधकर्ताओं ने जिन क्रस्टेशियन जीवों का अध्ययन किया वे अप्रत्याशित रूप से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यह खूबी उन्होंने अपने धीमे उपापचय की वजह से हासिल की है। वैज्ञानिकों का खयाल है कि कठोर माहौल में रहने के कारण शायद इन जीवों ने अपने शरीर को इस तरह से ढाला है। कार्बन-14 एक रेडियोएक्टिव कार्बन है। वायुमंडल में नाइटोजन के साथ ब्रह्मांडीय किरणों की क्रिया से यह रेडियोएक्टिव कार्बन कुदरती रूप से निर्मित होता है।

वैज्ञानिक सभी जीवों में इसे डिटेक्ट कर सकते हैं और इसका उपयोग पुरातात्विक और भौगोलिक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए करते हैं। 1950 और 1960 के दशकों में ताप-आण्विक हथियारों के परीक्षणों के पश्चात वायुमंडल में कार्बन-14 की मात्रा दोगुनी हो गई। इसकी वजह यह थी कि बमों से निकलने वाले न्यूट्रॉन कणों ने वायुमंडल में नाइट्रोजन के साथ क्रिया की। 1960 के दशक के मध्य में बम कार्बन का स्तर चरम पर पहुंच गया था। वायुमंडल में परमाणु परीक्षण बंद किए जाने के बाद ही इसके स्तर में गिरावट आई। 1990 के दशक तक वायुमंडल में कार्बन-14 का स्तर गिर कर परीक्षण-पूर्व स्तर से करीब 20 प्रतिशत ऊपर रह गया था। बम कार्बन तेजी से वायुमंडल से नीचे गिर कर समुद्री सतह में जा मिला। इससे साफ है कि समुद्र की सबसे गहरी खाइयां भी मनुष्य की गतिविधियों से अछूती नहीं हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

गिन गिन के गाली....

लोकसभा के इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां गिन-गिन कर गालियां दे रहीं हैं। गालियों के इस शब्दकोश में महारत हासिल करना भी किसी बड़ी काबिलियत से कम नहीं है। एक दूसरे पर गालियों की बौछार में भी कांटे की टक्कर हो रही है। उनकी गिनती भी हो रही है। आखिर चुनाव के बाद मतगणना के साथ गाली गणना भी तो होनी है। तभी तो गालियों का हिसाब-किताब सही से किया जा सकेगा और उसके असर का आकलन हो पाएगा। इसके बाद नतीजे भी आएंगे जिनमें कहा जाएगा 'चुनावी गालियों की कड़ी टक्कर में अमुक ने अमुक को 36 के मुकाबले 56 गालियों से मात दी, लेकिन वोटों की लड़ाई में मात खा गए। राजकाज की इस चुनावी जंग को अपनी गालियों के कारण याद किया जाएगा। दरअसल, गालियां सिर्फ आहत करने के लिए नहीं दी जातीं, बल्कि गालियां सम्मान की सूचक भी हैं, जो अपने प्रिय के लिए भी दी जाती हैं।

उड़ी हुई है नींद

सात चरणों के चुनाव में जिसका सबसे अंत में मतदान होना है वे तो फंसे ही हैं, लेकिन जिनका चुनाव पहले ही निपट गया है वे भी कम परेशान नहीं। दरअसल चुनाव से फारिग हो चुके उम्मीदवारों का रोजाना अलग-अलग अटकलों से सामना हो रहा है। इससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा में चुनाव से निपट चुके उम्मीदवारों के लिए ज्यादा संकट है। वे दिल से तो चाहते हैं कि अभी से दिल्ली की परिक्रमा शुरू कर दी जाए कि मंत्रिमंडल गठन की संभावना में अपने लिए भी कुछ जगह तलाश सकें। लेकिन ऐसी कवायद में आलाकमान उन्हें घरेलू मोर्चा संभाले रखने की हिदायत दे रहा है और घर में उनकी नींदें उड़ी हुई हैं।

कुर्सी की आस

लोकसभा की अधिकांश सीटों पर चुनाव हो चुका है। इसलिए नेताओं ने दिल्ली लौटना शुरू कर दिया है। जो नेता खुद अपनी और पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं, उन्होंने तो बाकायदा शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू कर दी है। कई नेता बंद गला कोट सिलवा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। वहीं कई अन्य नेताओं ने संसद सदस्य और मौका मिलने पर मंत्री के रूप में शपथ लेने के समारोह में अपने निकटवर्ती लोगों को बुलाने की योजना भी बनानी शुरू कर दी है। कई नेता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने लुटियंस जोन के आस-पास गेस्ट हाउस या होटल की बुकिंग भी कर दी है। बहरहाल नेताजी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। उनके अरमान पूरे होंगे या नहीं यह तो 23 मई को ही पता चलेगा।

भेदिए की तलाश

चुनाव आयोग इन दिनों किसी 'घर के भेदी' को तलाश रहा है जिसने उसकी किरकिरी करा दी है। बंद कमरे की 'अत्यंत' गोपनीय जानकारी के बाहर लीक हो जाने से आयोग असहज हो गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सदस्यों के बीच आमराय न बनने की खबर बाहर आ गई। किसी मुद्दे पर आयोग में मतभेद होना आम बात है, लेकिन परंपरा यही रही है कि ऐसी बातें बाहर नहीं आतीं। लेकिन इस बार लीक हुई सूचना अखबारों की सुर्खियां तक बन गई, जो उसे अखर रही है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के सभी मामलों में क्लीन चिट देना न देना आयोग का अधिकार है। मगर इस बैठक की यह सूचना बाहर आ गई कि एक सदस्य ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया। वैसे आयोग में पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसने अंदरूनी समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। आयोग इसे अंदरूनी मामले में दखल के तौर पर देख रहा है। हालांकि ऊंचे ओहदे वाले अफसर इसे ठंडा करने में जुटे हैं, लेकिन एयर कंडीशन में भी उन्हें ऐसा करने में पसीने छूट रहे है। चढ़े सियासी पारे की तपिश अब आयोग में भी महसूस हो रही है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।